जिलों में राजस्व वसूली के गम्भीर प्रयास किये जाए

जयपुर, 27 जुलाई। प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों के सभी सर्किल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये है कि वे छीजत कम करने के साथ ही राजस्व वसूली में बढ़ोतरी करने के काम में मुस्तैदी दिखाए और इस कार्य में जो भी परेशानियां आ रही है उन्हें अपने स्तर पर दूर करने का प्रयास करे।

अधीक्षण अभियन्ताओं को यह निर्देश बुधवार को वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया इसमें बताया गया कि छीजत और वित्तीय हानि कम करने के लिए वितरण निगमों के अध्यक्ष श्रीमत पाण्डेय ने एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है जिसकी पालना सुनिश्चित की जाए ताकि राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय मल्होत्रा ने इस बात पर चिन्ता जताई कि वित्तीय हानि में राजस्थान के तीनों विद्युत वितरण निगमों का काम देश भर मे नीचे से दूसरा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में राजस्व वसूली में मात्र 2 से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जो सन्तोषजनक नही है, इसके मुकाबले बिजली की खपत में निरन्तर बढ़ोतरी होती जा रही है। मल्होत्रा ने कहा कि अकेले जोधपुर डिस्कॉम में बिजली की खपत 15 प्रतिशत तक बढी है और इस तरह की वृद्धि जयपुर और अजमेर डिस्कॉम में भी हुई है लेकिन राजस्व वसूली में सुधार नही हुआ है। उन्होने सभी अभियन्ताओं से अनुरोध किया कि इन हालत को बदले और डिस्कॉम अध्यक्ष ने जो दिशा निर्देश जारी किये है उनका सही भावना से पालन करके राजस्व बढ़ोतरी के गम्भीर प्रयास करे।

राज्य सरकार के ऊर्जा सलाहकार आर.जी. गुप्ता का सुझाव था कि फीडर इंचार्ज सहायक राजस्व अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता और विजीलेंस अधिकारियों के रिक्त पदों को भर के काम किया जाए तो छीजत कम करने व राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते है। गुप्ता का कहना था कि उपखण्ड स्तर पर सहायक अभियन्ता पर से राजस्व वसूली का दायित्व कम करके यह दायित्व सहायक राजस्व अधिकारी को दिया जाए और खण्ड स्तर पर सहायक लेखाधिकारी–राजस्व की नियुक्ति कर दी जाए तो बेहतर परिणाम आ सकते है।

डिस्कॉम अध्यक्ष श्रीमत पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी तीन महीनें में सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर ओर ईमेल आईडी संकलित करने का कार्य किया जाए जिससे की बिल व अन्य प्रकार की सूचनाएं उपभोक्ताओं को मेसेज की जा सके। इसके साथ ही टास्क फोर्स की बैठक में यह सुझाव आया कि उपभोक्ताओ को दो महीने के स्थान पर प्रति माह बिल भेजा जाए इसके लिए आगामी 6 महीने में आवश्यक सभी कार्यवाही की जाए।

डिस्कॉम अध्यक्ष ने वीडियों कॉन्फ्रेंस में अत्यधिक छीजत वाले जिलों के अधीक्षण अभियन्ताओं से जानकारी चाही कि राजस्व वसूली बढाने के लिए वे क्या कदम उठा रहे है। एक जिले के अधीक्षण अभियन्ता से सन्तोषप्रद जवाब नही मिलने के बाद पाण्डेय ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्तकता को जिले में टीम भेजकर जांच करने के निर्देश दिये और वस्तु स्थिति की रिर्पाट शीघ्र देने को कहा।

पाण्डेय ने सभी जिला अधिकारियों से कहा वे नगरीय ओर औद्योगिक क्षेत्रों में छीजत को कम करने के लिए तत्परता से कार्य करे जिससे राजस्व वसूली में बढ़ोतरी हो सके। वीडियों कॉन्फ्रेंस मे कई जिलों से जानकारी मिली थी कि औद्योगिक क्षेत्रों में छीजत कम नही हो रही है।

.....